

मुकदमों का विवरण

तमिल नाडु और पुडुचेरी पेपर कप मैनुफैक्चर एसोसिएशन

वी.

तमिलनाडु राज्य और ओ. आर. एस. (सिविल अपील सं.) 18536 2022 आदि) 20 अक्टूबर, 2023

[एस. रवींद्र भाट और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय को 'प्रबलित' पेपर कप और गैर-बुने हुए प्लास्टिक बैग की निर्माण इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले अपीलकर्ता-संघ के नेतृत्व में रिट याचिकाओं को खारिज करने में न्यायसंगत ठहराया गया था, जिसमें प्लास्टिक लेपित चाय के कप और गैर-बुने हुए बैग के निर्माण, भंडारण, आपूर्ति, परिवहन, बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986। 5, 23 - प्लास्टिक लेपित चाय के कप और गैर-बुने हुए थैले-प्लास्टिक लेपित चाय के कप और गैर-बुने हुए थैलों के निर्माण, भंडारण, आपूर्ति, परिवहन, बिक्री, वितरण या उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला सरकारी आदेश-जिसे चुनौती दी गई-उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध को बरकरार रखा-हस्तक्षेप के साथ:

आयोजित किया गया: यद्यपि 1986 के नियम का अधिदेश तथ्यों पर पूर्वनिर्धारित सुनवाई का आह्वान करता है, समय के प्रभाव को देखते हुए, अधिसूचना में हस्तक्षेप की स्थिति में जनता को संभावित नुकसान, न्याय के हितों के लिए आवश्यक है कि इस तरह के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अधिसूचना को अमान्य नहीं किया जाना चाहिए-संरचना के अनुसार, प्लास्टिक लेपित चाय के कप गैर-जैव-अपघटनीय हैं, और उनके पुनर्चक्रण में भारी कठिनाई है, क्योंकि इसके लिए उचित संग्रह तंत्र, सख्त अलगाव की आवश्यकता होती है-यह देखते हुए कि प्रतिबंध के लिए वैज्ञानिक आधार है, और यह सार्वजनिक हित में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों की कई श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने का राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है, उच्च न्यायालय के साथ हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है। लेकिन आम जनता के व्यापक हित में प्रदूषण का आनंद लेने के लिए 1134

1133

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

अनुच्छेद 19 (6) के अनुसार प्रतिबंध उचित था, इस प्रकार, गैर-बुने हुए थैलों के संबंध में, संशोधित 2016 नियम अब 60 जी. एस. एम. से ऊपर के गैर-बुने हुए थैलों के निर्माण और उपयोग की अनुमति देते हैं-केंद्र ने इसे प्रतिबंधित करने के बजाय इसे विनियमित करने का एक तरीका खोज लिया है-इसे ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संशोधित 2016 नियम-पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986-प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के आलोक में गैर-बुने हुए थैलों के मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है।[पैरा 41,46,54]

सिद्धांत/सिद्धांत-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-पूर्व सुनवाई के नियम का अनुपालन-कब:

आयोजित किया गया: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन वहां किया जाना चाहिए जहां कानून उस पाठ्यक्रम की आवश्यकता करता है-प्राकृतिक न्याय के बारे में किसी कानून या नियम का मौन, फिर भी, न्यूनतम सुनवाई की मांग करता है-ऐसे मामले हैं, जहां अदालत निर्णयात्मक सुनवाई के बाद अनुमति देती है-ऐसी आपात स्थिति या तत्काल परिस्थितियां हो सकती हैं जो तत्काल या समीचीन कार्रवाई की मांग करती हैं, जिनमें देरी नहीं की जा सकती है-ऐसी स्थितियों में, पूर्व सुनवाई के नियम को समाप्त किया जा सकता है।[पैरा 39]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम एम. वी. नायडू (2001) 2 एस. सी. सी. 62:

[2000] 5 पूरक।एस. सी. आर. 249; बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड बनामसर शादी लाल

एंटरप्राइजेज लिमिटेड (2011) 1 एस. सी. सी. 640:[2010] 15 एससीआर 156; विक्टोरिया मेमोरियल

हॉल बनाम हावड़ा गणतंत्र नागरिक समिति और अन्य (2010) 3 एस. सी. सी. 732:

[2010] 3 एससीआर 190; बसवैया (डॉ.) बनाम डॉ. एच. एल. रमेश और अन्य। (2010)

8 एससीसी 372:[2010] 9 एस. सी. आर. 227; सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

ओआरएस., बनाम ट्राई (2016) 7 एससीसी 703:[2016] 9 एससीआर 1; एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (2004) 12 एससीसी 118:[2004] 3 एससीआर 126; एपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रो.एम. नायडू (सेवानिवृत्त) और अन्य (2001) 2 एससीसी 62:[2000] 5 पूरक।एससीआर

249; सद्भावना प्लास्टिक उद्योग बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 2013 एससीसी ऑनलाइन एनजीटी 71; एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ (1997) 1 एससीसी 388:[1996] 10 पूरक।एस. सी. आर. 12; पर्यावरण संरक्षण संगठन बनाम राज्य

केरल (2013) 7 एस. सी. सी. 226:[2013] 7 एस. सी. आर. 352; फोमेंटो रिसॉर्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड बनाममिंगुएल मार्टिन्स (2009) 3 एससीसी 571:[2009] 3 एस. सी. आर.; एम.

बिल्डर्स (पी) लिमिटेड बनामराधेन श्याम साहू (1999) 6 एस. सी. सी. 464:[1999] 3 एस. सी. आर. 1066; लिबर्टी ऑयल मिल्स बनाम भारत संघ (1984) 3 एस. सी. सी.

465:[1984] 3 एस. सी. आर. 676; धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड बनाम.सीसीई (2015) 8 एससीसी 519:[2015] 6 1135

तमिल नाडु और पुडुचेरी पेपर कप मैनुफैक्चर एसोसिएशन बनाम तमिल नाडु राज्य 1136

एस. सी. आर. 437; कर्नाटक एस. आर. टी. सी. बनाम एस. जी. येदियुरप्पा (2005) 3 एस. सी. सी. 409:[2005] 2 एससीआर 520; पी. पी. अग्रवाल बनाम भारतीय स्टेट बैंक (2006) 8 एससीसी 776:[2006]

1 पूरक।एस. सी. आर. 454-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 8536।2019 के डब्ल्यू. पी. No.3984 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 11.07.2019 से।

के साथ

2022 की सिविल अपील संख्या 8537-8538।

रूप:

बालाजी सुब्रमण्यन, ए. लक्ष्मीनारायणन, सुश्री शोभा राममूर्ति, शिल्प विनोद, एम. ए. कार्तिक, सुश्री रितिका राव, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।शोभित द्विवेदी, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., एम. योगेश कन्ना, विनोद कन्ना बी., रजत नायर, निशेष शर्मा, अशोक पाणिग्रही, शरत नांबियार, सुश्री रुचि कोहली, नकुल चेंगप्पा के. के., टी. एस. सबरिश, संदीप के. महापात्रा, अमरीश कुमार, गुरमीत सिंह मक्कर, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश एस. रवींद्र भाट, जे.

1. इन अपीलों पर पक्षकारों की सहमति से सुनवाई की गई।अपीलार्थी मद्रास उच्च न्यायालय के एक सामान्य निर्णय 1 से व्यथित हैं, जिसके द्वारा 'एक बार उपयोग और फेंकने वाले प्लास्टिक' के निर्माण, भंडारण, आपूर्ति, परिवहन, बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेश 2 को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।इससे पहले के अपीलार्थी

1 डब्ल्यू. पी. सं. 3984/2019 में दिनांकित 11.07.2019 निर्णय।

2 G.O.Ms संख्या 84 दिनांकित 25.06.2018 W. E. F. 01.01.2019 (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

न्यायालय एक संगठन है जो क्रमशः 'प्रबलित' कागज के कप के निर्माण में शामिल विनिर्माण इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, और गैर-बुने हुए प्लास्टिक बैग का निर्माता है।

तथ्य।

2. तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण और वन विभाग ने 25.06.2018 पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 ('EPA') की धारा 5 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकारी आदेश जारी किया और इसे 01.01.2019 से प्रभावी होना था। सरकारी आदेश में "उपयोग और फेंकने वाले प्लास्टिक" के निर्माण, भंडारण, आपूर्ति, परिवहन, बिक्री, वितरण या उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश शामिल थे-जिसमें स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक एफ. एल. ए. जी., भोजन को लपेटने के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की चादरें, भोजन की मेज पर फैलाना आदि शामिल थे। उल्लेखनीय है कि गैर-बुने हुए थैलों का स्पष्ट रूप से तब तक उल्लेख नहीं किया गया था जब तक कि राज्य सरकार द्वारा जारी एक स्पष्टीकरण दिनांक 08.12.2018 ने उन्हें प्रतिबंध के दायरे में नहीं लाया।

3. इन निर्देशों में एस. ई. जेड. या ई. ओ. यू. में किसी उद्योग द्वारा विशेष रूप से निर्यात उद्देश्यों के लिए उत्पादित प्लास्टिक कैरी बैग; प्लास्टिक बैग जो पैकेजिंग का एक अभिन्न हिस्सा हैं या बनाते हैं जिसमें विनिर्माण/प्रसंस्करण इकाइयों में उपयोग करने से पहले माल को सील कर दिया जाता है; सरकारी विभागों के आदेशों के खिलाफ वानिकी और बागवानी नर्सरी में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक बैग और चादरें; डेयरी उत्पादों, तेल, दवा और चिकित्सा उपकरणों को पैक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक; और "कम्पोस्टेबल प्लास्टिक" से बने कैरी बैग 3 (नियमों के अनुसार) के लिए भी छूट दी गई है। 4 सरकारी आदेश के अनुसार, तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन अधिसूचना की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए किया गया था।

3 व्याख्या के लिए स्पष्टीकरण 5 देखें।

4 मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान, सरकारी आदेश में और संशोधन किए गए हैं; अधिसूचना दिनांक 05.06.2020 द्वारा, राज्य ने प्रसंस्करण इकाइयों में उपयोग से पहले सीलबंद माल की पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक बैगों के लिए छूट को हटा दिया, और प्रभाव अधिनियम में एक और निर्देश जोड़ा कि उपयोग और फेंकने वाले प्लास्टिक (कम्पोस्टेबल प्लास्टिक के अलावा) के विकल्पों की जांच और परीक्षण केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET) द्वारा किया जाएगा और तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

4. अपीलार्थी पेपर कप संघ ने 05.09.2018 पर सरकार को पुनर्विचार करने और उन्हें प्रतिबंध से बाहर करने के लिए एक अभ्यावेदन दिया। इसके अनुसार, पेपर कप और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक के कम्पोस्टेबल गुणों का अध्ययन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति ने एल. डी. पी. ई. लेपित पेपर कप और वैकल्पिक बायोप्लास्टिक के गुणों पर चर्चा की जो बायोडिग्रेडेबल थे। इसने निष्कर्ष निकाला कि एल. डी. पी. ई. ने ऐसे कपों को गैर-जैव-अपघटनीय, लेकिन पुनर्नवीनीकरण योग्य बनाया। हालांकि, अपर्याप्त संग्रह तंत्र या विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी की विफलता के कारण-उनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा रहा है।

5. याचिकाकर्ता संघ को 14.11.2018 पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी आमंत्रित किया गया था, जिसके दौरान उन्होंने तर्क दिया कि अन्य राज्यों (जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा) में प्रबलित पेपरकप के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, जिन्होंने 'प्लास्टिक प्रतिबंध' भी लागू किया था। टी. एन. पी. सी. बी. द्वारा 08.12.2018 पर संघ के प्रतिनिधित्व को दो आधारों पर खारिज कर दिया गया था: सबसे पहले, कि एक बार उपयोग किए जाने वाले और फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की यह नीति प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (इसके बाद '2016 नियम') के आलोक में पर्यावरण की रक्षा के लिए थी; और दूसरा, कि विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्ष निकाला था कि उत्पाद की संरचना, प्राकृतिक पर्यावरणीय परिस्थितियों में खराब होने के लिए इसे कठिन बनाती है।

6. इसी तरह, गैर-बुने हुए थैले संघ ने भी टी. एन. पी. सी. बी. को 23.08.2018 और 19.09.2018 पर अभ्यावेदन दिया, जिसे टी. एन. पी. सी. बी. द्वारा जारी स्पष्टीकरण और राज्य सरकार द्वारा जारी एक और विस्तृत स्पष्टीकरण के माध्यम से 08.12.2018 5 पर इसी आधार पर खारिज कर दिया गया कि ऐसे गैर-बुने हुए थैलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तर्क यह दिया गया था कि ऐसे थैले पॉलीप्रोपाइलीन से बने होते हैं, और प्राकृतिक वातावरण में आसानी से खराब नहीं होते हैं।

7. प्रतिबंध से व्यथित, पेपर कप संघ ने एनजीटी के समक्ष अधिसूचना को चुनौती दी, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि चुनौती एनजीटी के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं थी।

5 सी. आई. पी. ई. टी. रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि "पॉलीप्रोपाइलीन एक सिंथेटिक प्लास्टिक है जिसे गैर-बुने हुए कपड़े के रूप में रासायनिक या विलायक उपचार द्वारा एक साथ बुना जाता है।"

6 एनजीटी, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष अपील डायरी संख्या 05/2018 में दिनांकित 28.01.2019 आदेश।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

8. उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र में पहुंचते हुए, अपीलकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अपने अधिकारों का हवाला दिया। उनके मुख्य आधार थे: सबसे पहले, कि राज्य द्वारा जिन रिपोर्टों पर भरोसा किया गया था, उन्होंने माना कि कागज के कप पुनर्नवीनीकरण योग्य थे बशर्ते कागज और एल. डी. पी. ई. प्लास्टिक परत को अलग

किया गया हो (जिसे संघ सहायता/समर्थन करने के लिए तैयार था), और यह उत्पाद अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के समान नहीं था। इस बात पर भी जोर दिया गया कि यह कार्रवाई बिना किसी समझदारी के की गई और इसका 5 से 6 लाख कर्मचारियों की आजीविका पर व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (इसके बाद '1986 नियम') के नियम 4 में एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित करने, आपत्तियों को आमंत्रित करने और इन पर विचार करने के बाद एक वित्तीय अधिसूचना पारित करने के लिए अनिवार्य परामर्श तंत्र का पालन नहीं किया गया।

9. गैर-बुने हुए थैले उद्योग की ओर से तर्क दिया गया था कि ये थैले पानी और हवा पारगम्य थे, और इसलिए नालियों को बंद नहीं करते थे। वे पर्यावरण के अनुकूल विकल्प थे जिनका 10 से अधिक बार उपयोग किया जा सकता था और पुनर्नवीनीकरण योग्य थे; उन्हें दुनिया में कहीं और प्रतिबंधित नहीं किया गया था और उनका व्यापक उपयोग और अनुप्रयोग था।

10. उच्च न्यायालय ने प्लास्टिक उद्योगों के अन्य पीड़ित निर्माताओं के नेतृत्व में विभिन्न याचिकाओं के साथ रिटों पर सुनवाई की और प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए सामान्य निर्णय द्वारा उन्हें खारिज कर दिया।⁷ यह अन्य न्यायालयों (अर्थात्, दिल्ली उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश न्यायालय 8, एन. जी. टी. 9) के साथ सहमत था क्योंकि उसने अपने नीतिगत निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए ई. पी. ए. की धारा 5 के तहत ऐसे सरकारी आदेश पारित करने की राज्य की क्षमता को सही ठहराया था; जिसकी न्यायिक समीक्षा सीमित थी।¹⁰ गैर-बुने हुए थैलों के सवाल पर,

7 उच्च न्यायालय ने नोट किया कि विभिन्न अन्य रिट याचिकाएं (डब्ल्यू. पी. सं. 34065/2018 डी. डी.)। 27.12.2018, डब्ल्यूपी सं. 24623/2018 डीडी। 19.12.2018, डब्ल्यूपी (एम. डी.) सं. 10131/2018 डीडी। 03.12.2018) या तो विवादित सरकारी आदेश की वैधता को चुनौती दी गई, या इसके कार्यान्वयन की मांग को अदालत की समन्वय पीठों द्वारा खारिज कर दिया गया।

8 लोकप्रिय प्लास्टिक और ओआरएस. वी. मध्य प्रदेश राज्य, डब्ल्यूपी सं. 8182/2017 डीडी।

06.09.2018

9 के. के. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रा. लि. और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, अपील

नं. 117/2016।

10 अदालत ने आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम एम. वी. नायडू [(2001) 2 एस. सी. सी. 62] और बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड बनाम. सर शादी लाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड [(2011) 1 एससीसी

640] उत्तराखंड ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक समीक्षा नीति के मामलों में सीमित थी।

1139

तमिल नाडु और पुडुचेरी पेपर कप मैनुफैक्चर एसोसिएशन बनाम तमिल नाडु राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1140

अदालत ने कहा कि चूंकि वे गैर-जैव-अपघटनीय थे, इसलिए उनकी पुनः प्रयोज्य रोगजनक संचरण का जोखिम ले जाती है, और थैलों में वर्षा संक्रमण और भूजल निर्वहन में कमी लाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि वे पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग विकल्प थे; राज्य ने सी. आई. पी. ई. टी. के एक अध्ययन के अनुसार उन पर प्रतिबंध लगा दिया

था। यह देखते हुए कि अदालत पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञ नहीं है, सामग्री 11 से अधिक परिचित विशेषज्ञों के निर्णय को सम्मान देना पड़ा और इसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं में नहीं लिया जा सका। कप के संबंध में, यह नोट किया गया था कि उनका अंधाधुंध उपयोग किया जाता है और एकल उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है, बड़ी मात्रा में जमा होता है, और आंखों में दर्द होता है; क्योंकि वे एक बार प्लास्टिक का उपयोग करते हैं और फेंकते हैं, इसलिए प्रतिबंध को उचित ठहराया गया था।

11. अपीलकर्ता इस अदालत के हस्तक्षेप की मांग इस आधार पर करते हैं कि सामान्य निर्णय उनके द्वारा की गई विशिष्ट दलीलों और विचाराधीन उत्पादों पर विचार किए बिना पारित किया गया था।

याचिकाकर्ताओं की दलीलें

12. अपीलकर्ता-संघ की ओर से पेश वकील ने आग्रह किया कि प्रबलित कागज के कप (विवादित अधिसूचना में "प्लास्टिक लेपित चाय के कप" के रूप में संदर्भित) प्लास्टिक के कप के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प थे क्योंकि उनकी संरचना 94 प्रतिशत खाद्य श्रेणी के कागज की थी और एलडीपीई की केवल 6 प्रतिशत परत थी जो कप को मजबूत करने और इसे जल प्रतिरोधी बनाने के लिए आवश्यक है। एक बार जब कागज और प्लास्टिक अलग हो जाते हैं, तो कागज पुनर्नवीनीकरण और जैव अपघटनीय दोनों होता है, जबकि एल. डी. पी. ई. पुनर्नवीनीकरण और विभिन्न उद्देश्यों के लिए पुनः प्रयोज्य होता है। यह बताया गया कि एम. एस. एम. ई. क्षेत्र के निर्माता टी. एन. पी. एल., आई. टी. सी. आदि पेपर मिलों से एल. डी. पी. ई. कोटिंग वाला पेपर खरीदते हैं और उनका उपयोग कप बनाने के लिए करते हैं।

13. अपीलार्थी की प्रस्तुतियाँ मुख्य रूप से दो तख्तों पर थीं-पहला यह कि प्रतिबंध के लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, जिसने एक मनमाना वर्गीकरण बनाया; और दूसरा, कि 1986 के नियमों का गैर-अनुपालन था, जो विवादित अधिसूचना जैसे आदेश को पारित करने से पहले मसौदा नियमों के प्रकाशन और आपत्तियों को आमंत्रित करने को अनिवार्य करता है। वकील ने तर्क दिया कि

11 न्यायालय ने सचिव और क्यूरेटर, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाम हावड़ा गणतांत्रिक नागरिक समिति और अन्य, (2010) 3 एस. सी. सी. 732 पर भरोसा किया। बसवैया (डॉ.) बनाम डॉ. एच. एल. रमेश और

ओआरएस., (2010) 8 एससीसी 372।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

वर्गीकरण-एल. डी. पी. ई. कोटिंग के साथ पेपर कप को अन्य उत्पादों के साथ शामिल करना जो बड़े पैमाने पर प्लास्टिक से बने होते हैं-मनमाना और अन्यायपूर्ण था। यह भी रेखांकित किया गया कि अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त उत्पाद वास्तव में पर्यावरण के लिए कहीं अधिक हानिकारक हैं, जिस पर उच्च न्यायालय ने भी ध्यान दिया।

14. राज्य द्वारा भरोसा की गई तीन रिपोर्टों को संबोधित करते हुए-अपीलार्थी की ओर से पेश वकील ने बताया कि इन तीन रिपोर्टों में से किसी ने भी प्रबलित पेपर कप पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश नहीं की। वास्तव में आई. आई. टी. की रिपोर्ट में प्लास्टिक कप के विकल्प के रूप में पेपर कप के उपयोग की सिफारिश की गई थी; विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि पेपर कप पर एल. डी. पी. ई. कोटिंग को पेपर मिलों में पल्लिंग और स्क्रीनिंग प्रक्रिया में अलग किया जा सकता है, जिसमें यह आग्रह किया गया था कि यह एक आम प्रथा है जिसके परिणामस्वरूप पेपर और एल. डी. पी. ई. दोनों ही पुनर्नवीनीकरण योग्य हैं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए पुनः प्रयोज्य हैं; और जबकि सी. आई. पी. ई. टी. की रिपोर्ट में पेपर कप की भौतिक विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया गया है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि यह 'पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता है' जैसा कि उच्च न्यायालय ने गलती से निष्कर्ष निकाला है।

15. वकील ने प्रत्यायोजित कानून जारी करने से पहले पूर्व परामर्श करने की विफलता पर काम किया। प्रकृति में निर्देशिका के बजाय एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 4 पर जोर दिया गया था। इसलिए, राज्य को इसका जवाब देने के लिए कम से कम 15 दिनों की अवधि के साथ एक मसौदा या प्रस्तावित अधिसूचना जारी करनी थी, जिसके बाद उठाई गई आपत्तियों से निपटने के लिए एक लिखित आदेश जारी किया गया था। सेल्युलर में इस अदालत के फैसले पर रिलायंस को रखा गया था।

ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस, बनाम ट्राई 12.

16. वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय कप की 'अवमूल्यनशीलता' पर एक गलत धारणा पर आगे बढ़ा था। हालाँकि, सवाल इसके बजाय 'पुनर्चक्रण' का है। उस कागज और एल. डी. पी. ई. कोटिंग को कागज मिलों में अलग किया जा सकता है, विवाद में नहीं है; एक संग्रह तंत्र का अभाव वह समस्या थी जिसके लिए कुल प्रतिबंध एक असमान समाधान था। प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 2016 के नियम 6 का हवाला देते हुए, एक संग्रह तंत्र बनाने और स्थापित करने की जिम्मेदारी नगर निगमों को दी गई थी। ऐसा करने में विफलता, अपीलार्थियों के अपना व्यवसाय करने के अधिकार में बाधा नहीं डाल सकती है। इसके बिना

12 (2016) 7 एससीसी 703 [पैरा 74]।

1141

तमिल नाडु और पुडुचेरी पेपर कप मैन्युफैक्चर एसोसिएशन बनाम तमिल नाडु राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1142

अपना मामला स्वीकार करते हुए, वकील ने उपयोग किए गए कप की पुनर्खरीद योजना के माध्यम से संग्रह तंत्र में सुधार के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपीलकर्ताओं की इच्छा व्यक्त की।

17. अंत में, वकील ने प्रस्तुत किया कि तमिलनाडु राज्य और उसके निवासियों द्वारा डिस्पोजेबल कप पर बड़े पैमाने पर निर्भरता है और स्थानीय उत्पादन पर प्रतिबंध के कारण, उन्हें अन्य राज्यों के निर्माताओं से लाया जा रहा है जिसमें इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद इस बड़े पैमाने पर उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई। वकील ने दोहराया कि

प्रबलित कप, प्लास्टिक कप का एकमात्र पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हैं, और उनके निर्माण पर प्रतिबंध लगाने से केवल छोटे दुकानदारों और एमएसएमई उद्यमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिन्हें विशेष रूप से ऋण और अन्य योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा बढ़ावा और समर्थन दिया जाता है। इन तथ्यों के आलोक में, यह आग्रह किया गया कि उचित व्यक्ति के परीक्षण को विकास और पर्यावरण को संतुलित करने और सख्त सुरक्षा उपायों के साथ निर्माण की अनुमति देने के लिए लागू किया जाना चाहिए। रिलायंस को इस अदालत के फैसले पर रखा गया था

एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ 13.

18. गैर-बुने हुए कैरी बैग के निर्माता की ओर से वकील ने तर्क दिया कि ऐसे बैग साड़ी, शर्ट आदि के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले पॉलिएस्टर फाई विलाप के समान स्पन-बॉन्डिंग फाई ब्रेस द्वारा पॉली-प्रोपलीन ग्रेन्युल्स से बने होते हैं; और गैर-बुने हुए कपड़ों का व्यापक उपयोग होता है। इनकी रासायनिक संरचना कमजोर होती है और ये मोनो-पॉलिमर से बने होते हैं, जिससे इन्हें अलग करना और रीसायकल करना आसान हो जाता है। गैर-बुने हुए पॉलीप्रोपाइलीन कैरी बैग प्लास्टिक बैग के पुनः प्रयोज्य विकल्प हैं। इनमें कपड़े जैसी संरचना होती है जिसमें हवा और पानी पारगम्यता होती है। इसलिए, भले ही गैर-बुने हुए कैरी बैग को फेंक दिया जाए, लेकिन पानी के चैनल, नालियों, सीवर लाइनों आदि के अवरुद्ध होने या बंद होने और मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। ये कपड़े रासायनिक रूप से निष्क्रिय और गैर-विषैले होते हैं और इसलिए, इन सामग्रियों को जलाने से भी कोई जहरीली गैस या प्रदूषक पैदा नहीं होंगे। गैर-बुने हुए थैले सूरज की रोशनी और बारिश के संपर्क में आने पर विघटित हो जाते हैं और 100 दिनों के भीतर भी खराब हो सकते हैं। यहां तक कि सी. आई. पी. ई. टी. द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट में भी यह तर्क दिया गया था कि

13 (2004) 12 एससीसी 118।

14 गैर-बुने हुए कपड़ों के कई अनुप्रयोग हैं-चिकित्सा (सर्जिकल गाउन, फेस मास्क, जूता कवर, टोपी, आदि), फिल्टर (वैक्यूम बैग, हेपाफी परिवर्तन), कृषि (छाया जाल, फसल कवर, मिट्टी लाइनर, चाय बैग, आदि), और पैकेजिंग (जहां छिद्रता की आवश्यकता होती है, सभी प्रकार के बैग जैसे डब्ल्यू. सी. यू. टी., डी. सी. यू. टी., मॉल, कपड़ा, खुदरा आदि में उपयोग किए जाने वाले हैंडल लूप बैग)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

साबित किया कि गैर-बुने हुए कैरी बैग 100% पर्यावरण के अनुकूल हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किए गए जीवन चक्र मूल्यांकन अध्ययन से पता चलता है कि गैर-बुने हुए कैरी बैग प्लास्टिक के लिए वास्तविक विकल्प और विकल्प हैं, क्योंकि वे प्रकृति में छिद्रपूर्ण हैं और हवा और पानी स्वतंत्र रूप से गुजर सकते हैं, और पुनर्चक्रण कागज और प्लास्टिक में एक वास्तविक वैश्विक तापमान वृद्धि प्रभाव है।

19. वकील ने बताया कि गैर-बुने हुए कैरी बैग कपड़े को भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा तकनीकी वस्त्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा, गैर-बुने हुए पॉलीप्रोपाइलीन कैरी बैग का निर्माण ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है और पॉलीप्रोपाइलीन का कोई प्रतिशत नहीं है, यानी सभी गैर-बुने हुए कैरी बैग में 98.2% पॉलीप्रोपाइलीन नहीं होता है। यह तर्क दिया गया कि गैर-बुने हुए कैरी बैग में पॉली प्रोपलीन का कम प्रतिशत होता है, जो 57 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक भिन्न होता है, जबकि एक औसत कैरी बैग का उत्पादन 30 प्रतिशत से 90 प्रतिशत पॉलीप्रोपाइलीन के साथ किया जा सकता है; और यह कि अपीलकर्ता इस न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किसी भी प्रतिशत के साथ गैर-बुने हुए कैरी बैग का निर्माण करने के लिए तैयार हैं। इस तरह, राज्य गैर-बुने हुए कैरी बैग में जी. एस. एम. के प्रतिशत को गुणा करके पॉलीप्रोपाइलीन के अनुपात को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन इसे 'एक बार उपयोग और फेंक' के रूप में ब्रांडिंग करके पूर्ण प्रतिबंध या निषेध अनुचित और असमान था।

20. यह तर्क दिया गया था कि इस तरह के प्रतिबंध से भारी बेरोजगारी पैदा हुई और खरीदी गई मशीनरी बेकार हो गई क्योंकि उनका उपयोग केवल गैर-बुने हुए कैरी बैग बनाने के लिए किया जा सकता था, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। इसलिए, विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि विवादित प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन है। इसके अलावा, वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य सरकार ने सरकार द्वारा प्रचारित विभिन्न कौशल-विकास और उद्यमिता कार्यक्रमों के एक हिस्से के रूप में ऐसे छोटे उद्यमों के साथ समझौते किए थे, जो गैर-बुने हुए थैलों का निर्माण कर रहे थे।

21. यह भी प्रस्तुत किया गया कि गैर-बुने हुए पॉलीप्रोपाइलीन का उपयोग 2016 के नियमों के संदर्भ में डायपर, सैनिटरी नैपकिन आदि सहित विभिन्न चिकित्सा, औद्योगिक और अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है और वे गैर-बुने हुए कैरी बैग की तुलना में बहुत अधिक प्रतिशत मूल्य प्रदर्शित करते हैं। जबकि उपचार विधियों के साथ अन्य पॉली-प्रोपलीन उत्पादों के निपटान की अनुमति है, यदि और जब निर्धारित किया जाता है, तो यह आग्रह किया गया कि उसी तर्क को 1143 तक बढ़ाया जा सकता है।

तमिल नाडु और पुडुचेरी पेपर कप मैनुफैक्चर एसोसिएशन बनाम तमिल नाडु राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1144

गैर-बुने हुए पॉलीप्रोपाइलीन बैग भी। इसके अलावा, अपनी सुरक्षा को प्रदर्शित करने के लिए, वकील ने बताया कि पॉलीप्रोपाइलीन का उपयोग अक्सर चिकित्सा प्रत्यारोपण में, विशिष्ट सी सर्जरी आदि में एक गैर-अवशोषित, सिंथेटिक सीवन सामग्री के रूप में किया जाता है, जो साबित करता है कि यह मनुष्य के लिए कोई स्वास्थ्य खतरा पैदा नहीं करेगा। यह आगे तर्क दिया गया कि वैज्ञानिक अध्ययनों ने साबित किया कि फेंके गए थैलों का भी डामर वाली सड़कें बिछाने के लिए एक घटक के रूप में उपयोग किया जा सकता है; इस तकनीक का उपयोग सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा था। प्लास्टिक के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए पारिस्थितिक विकल्पों को अपनाने और लागू करने के बजाय, सरकार ने इस तरह के प्रतिबंध से पहले बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन के

जल्दबाजी में प्रतिबंध लगा दिया था।²² इसके अलावा, वकील ने तर्क दिया कि गैर-बुने हुए कैरी बैग को एक बार या एकल उपयोग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और वस्तुओं को फेंक दिया जा सकता है। इन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फेंक नहीं दिया जाएगा और यह दिखाने के लिए कोई डेटा भी नहीं है कि गैर-बुने हुए कैरी बैग पर्यावरण पर कोई प्रभाव डाल रहे हैं। यह देखते हुए कि उन्हें मुफ्त में वितरित नहीं किया जाता है, यह निष्कर्ष निकालना अधिक बाध्यकारी है कि लोग एकल उपयोग के बाद फेंक नहीं देंगे, और पुनः उपयोग करेंगे। इसके अलावा, अपशिष्ट पृथक्करण एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे नगर निगम के अधिकारियों या स्थानीय निकाय को पूरा करना होता है। यह सुनिश्चित करने के बजाय कि सरकार के उपकरण इस तरह के कर्तव्यों का कुशलता से निर्वहन कर रहे हैं, सरकार ने गैर-बुने हुए कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक छोटी विधि अपनाने का विकल्प चुना था। यदि वैज्ञानिक सी और नए तरीकों को अपनाकर अपशिष्ट पृथक्करण ठीक से किया जाता है, तो प्रतिबंध आवश्यक नहीं हो सकता है।

23. इसके अलावा, प्रतिबंध लगाने से पहले, हितधारकों से परामर्श नहीं किया गया था और समग्र रूप से निर्माताओं को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। भले ही कुछ संघों ने सरकार से संपर्क किया और अपनी आपत्तियां दीं, लेकिन यह तर्क दिया गया कि अपने आप में उन सभी हितधारकों को सुनने की आवश्यकता को समाप्त नहीं किया जा सकता है जिन्हें प्रतिबंध से पहले प्रभावित होने की संभावना है।²⁴ वकील ने यह स्थापित करने के लिए डेटा के अभाव पर भी तर्क दिया कि गैर-बुने हुए थैले वास्तव में कचरे में बहुत अधिक योगदान करते हैं। दूसरी ओर, यदि राज्य सूक्ष्म प्लास्टिक की अवधारणा को प्रभावी बनाने का इरादा रखता है, तो उन्हें अन्य उत्पादों (टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक वस्तुओं जैसे फेस वॉश, स्क्रब आदि) पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो सीधे समुद्री जीवन को प्रभावित करते हैं। हालाँकि, उन उत्पादों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन उसने केवल गैर-बुने हुए कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने का विकल्प चुना था और इसलिए, भेदभाव के आधार पर विवादित आदेश को दूषित कर दिया गया है। अपीलार्थियों के वकील ने आग्रह किया कि गैर-बुने हुए कैरी बैग का कोई विकल्प नहीं है और वे लकड़ी के बने नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

100% पॉलीप्रोपाइलीन। जूट, कागज और कपास के निर्माण के लिए पानी की खपत पॉलीप्रोपाइलीन के प्रभाव से कहीं अधिक है। रसायन जो पर्यावरण और मानव अस्तित्व के लिए अधिक विषाक्त और हानिकारक हैं, उनका उपयोग औद्योगिक उत्पादों, जैसे पारा और साइनाइड के निर्माण में किया जाता है, लेकिन उन्हें एफ. एल. आई. एम. एस. सी. और निराधार कारणों का हवाला देते हुए या तो प्रतिबंधित या निषिद्ध नहीं किया जाता है।

उत्तरदाताओं के तर्क

25. तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने ई. पी. ए. के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 23 (केंद्र सरकार की प्रत्यायोजित करने की शक्ति) और धारा 5 (निर्देश देने की शक्ति) पर

भरोसा किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि विवादित सरकारी आदेश राज्य सरकार की विधायी क्षमता के भीतर था जिसने इसे ई. पी. ए. की धारा 5 (केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित इस शक्ति के अनुसार) के तहत जारी किया था। यह तर्क दिया गया कि सत्ता के इस प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार को पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध सहित किसी भी उद्योग, संचालन, प्रक्रिया पर कड़े नियम लागू करने का अधिकार दिया। रिलायंस को एपी पर रखा गया था

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रो.एम. नायडू (सेवानिवृत्त) और अन्य। 15.

26. यह प्रस्तुत किया गया था कि विवादित सरकारी आदेश और 2016 के नियमों के बीच कोई असहमति नहीं थी क्योंकि वे अलग और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। नियम विनियामक उपायों को निर्दिष्ट करते हैं, जिनका अनुपालन इन नियमों के संदर्भ में प्लास्टिक निर्माताओं के लिए पंजीकरण के अनुदान के लिए आवश्यक है, जबकि विवादित अधिसूचना केवल कुछ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करती है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। उच्च न्यायालय ने इस स्थिति को सही ही स्वीकार किया था।¹⁶ रिलायंस को सद्भावना प्लास्टिक पर रखा गया था

उद्योग बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 17, जिसके खिलाफ दीवानी अपील,

इस अदालत ने इसका भी निपटारा कर दिया है।²⁷ वकील ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले स्वच्छ और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार पर काम किया और कहा कि यह अपीलार्थियों के वाणिज्यिक हितों से परे है। लोक विश्वास के सिद्धांत को वकील की दलीलों को समर्थन देने के लिए सेवा में लगाया गया था, और यह आग्रह किया गया था कि न्यायिक समीक्षा के मानक को अदालतों द्वारा लागू किया जाए जहां पर्यावरण

15 (2001) 2 एससीसी 62, पैरा 43।

16 विवादित उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 52 को देखें।¹⁷ 2013 एससीसी ऑनलाइन एनजीटी 71, पैरा 17।

1145

तमिल नाडु और पुडुचेरी पेपर कप मैन्युफैक्चर एसोसिएशन बनाम तमिल नाडु राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1146

आम जनता की सुरक्षा और हित एक दांव है, एक संकीर्ण है। वकील ने इस संबंध में कई मामलों की ओर इशारा किया।¹⁸

28. प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन पर अपीलार्थियों के तर्क का कड़ा विरोध किया गया था; वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दोनों अपीलार्थियों के प्रतिनिधित्व को प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा ध्यान में रखा गया था, और विचार-विमर्श में कई स्पष्टीकरण भी दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला था कि 1986 के नियमों के नियम 4 का कड़ाई से पालन मामले के विशेष तथ्यों में आवश्यक नहीं था और इस प्रतिबंध के बारे में भारी प्रचार किया गया था।¹⁹

29. वकील ने जोर देकर कहा कि अपीलकर्ता संघों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था; 14.11.2018 पर, संघों को संचालन समिति द्वारा सुनवाई के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया कि 'प्लास्टिक प्रतिबंध' स्थापित करने वाले अन्य राज्यों में पेपर कप

पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। यह उन्हें सुनने के बाद ही था कि 08.12.2018 दिनांकित स्पष्टीकरण किया गया था-जिसके द्वारा उनके प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया था।

30. गैर-बुने हुए पॉलीप्रोपाइलीन थैलों के संबंध में, राज्य ने इस तर्क का विरोध किया कि यह एक कपड़ा सामग्री थी न कि प्लास्टिक। सी. आई. पी. ई. टी. ने निष्कर्ष निकाला है कि यह "पॉलीप्रोपाइलीन, एक सिंथेटिक प्लास्टिक है जिसे फाइबर में बुना जाता है और गैर-बुने हुए कपड़े के रूप में रासायनिक या विलायक उपचार द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है।" इन थैलों में उपयोग की जाने वाली सामग्री उन्हें कठोर और जल प्रतिरोधी बनाती है। वे आसानी से टूट जाते हैं और अक्सर फेंक दिए जाते हैं। यह कहा गया था कि उच्च तापमान पर, पॉलीप्रोपाइलीन हानिकारक पदार्थों को छोड़ता है और यदि इसका उपयोग धीमी गिरावट प्रक्रिया के साथ लंबी अवधि में किया जाता है, तो संभावित संकट प्लास्टिक बैग की तुलना में अधिक खतरनाक है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी ने स्वयं दावा किया था कि यह गैर-बुना हुआ कपड़ा बहुत कम समय के भीतर सूर्य की रोशनी में खराब हो जाता है; यह भौतिक रूप से बहुत छोटे टुकड़ों में टूट जाता है (जिसे 'विघटन' कहा जाता है) और जैविक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, अकार्बनिक यौगिकों और जैव द्रव्य का उत्पादन करने के लिए खराब नहीं होता है और खाद योग्य प्लास्टिक (जो 'आईएस/आईएसओ 17088' में निहित है) के मामले में कोई भी स्पष्ट या विषाक्त अवशेष नहीं छोड़ता है। 2008 – कम्पोस्टेबल के लिए विशिष्ट कैटायन

18 एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ (1997) 1 एससीसी 388; पर्यावरण संरक्षण संगठन बनाम केरल राज्य (2013) 7 एस. सी. सी. 226 मीटर फोमेंटो रिसॉर्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड बनाम। मिंगुएल मार्टिन्स (2009) 3 एस. सी. सी. 571, एम. आई. बिल्डर्स (पी) लिमिटेड बनाम. राधेन श्याम साहू (1999) 6

एससीसी 464।

19 विवादित उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 56 को देखें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

प्लास्टिक')। इसलिए, छोटे टुकड़े (जिन्हें 'माइक्रोप्लास्टिक' के रूप में जाना जाता है और मिट्टी, ताजे पानी आदि में हो सकते हैं और ऐसे पारिस्थितिक तंत्र पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। रिलायंस को दिल्ली उच्च न्यायालय की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 8120/2009 20 और एनजीटी के आदेश 21 में पंजाब और हरियाणा राज्य में प्लास्टिक की थैलियों के प्रतिबंध और उपयोग के संबंध में टिप्पणियों पर रखा गया था, जिसमें गैर-बुने हुए थैले शामिल थे।

31. तीन रिपोर्टें (आई. आई. टी. मद्रास रिपोर्ट, विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट, और सी. आई. पी. ई. टी. द्वारा किए गए रासायनिक परीक्षण) की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और वकील ने आग्रह किया कि विवादित अधिसूचना विशेषज्ञ डेटा द्वारा समर्थित थी। यह तर्क देते हुए कि प्रतिबंध केवल प्लास्टिक के उपयोग और फेंकने के संबंध में है, चाहे वे पुनर्नवीनीकरण योग्य हों या गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य, क्योंकि उपभोक्ता इन उत्पादों को व्यापक रूप से फेंक देते हैं, और अनैतिक

रूप से कचरा फेंकते हैं, जिससे प्रभावी रूप से एकत्र करना, अलग करना और पुनर्नवीनीकरण करना असंभव हो जाता है। उच्च न्यायालय को इस आधार पर अपीलकर्ताओं की चुनौती को खारिज करने और यह अभिनिर्धारित करने में न्यायसंगत ठहराया गया कि प्रतिबंध वैज्ञानिक सी विश्लेषण पर रक्षात्मक है क्योंकि ये उत्पाद जैव-अपघटनीय नहीं थे।

विश्लेषण और निष्कर्ष

A. प्रासंगिक प्रावधान

32. ई. पी. ए. की धारा 5, निर्देश देने की शक्ति से संबंधित है:

“5. निर्देश देने की शक्ति-किसी भी बात के बावजूद

किसी अन्य कानून में निहित लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार, इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्यों के निष्पादन में, किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकरण को लिखित रूप में निर्देश जारी कर सकती है और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

स्पष्टीकरण-शंकाओं से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति में निर्देश देने की शक्ति शामिल है-(ए) किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया को बंद करना, निषेध करना या विनियमित करना; या (बी) बिजली या पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकना या विनियमित करना।”

20 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 8120/2009 में पारित दिनांकित 28.08.2009 निर्णय के पैराग्राफ 9 और 11।

21 मूल आवेदन संख्या 442/2015।

1147

तमिल नाडु और पुडुचेरी पेपर कप मैन्युफैक्चर एसोसिएशन बनाम तमिलनाडु राज्य 1148 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ई. पी. ए. की धारा 23 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु सहित कई राज्यों को अधिनियम की धारा 5 के तहत निहित अपनी शक्तियों को सौंप दिया। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार सभी या किसी भी राज्य सरकार के संबंध में शक्तियों के ऐसे प्रत्यर्पण को रद्द कर सकती है, या स्वयं अधिनियम की धारा 5 का आह्वान कर सकती है, यदि उसे जनहित के हित में ऐसी कार्रवाई आवश्यक लगती है।²²

33. 1986 के नियमों के नियम 4 को धारा 5 के साथ पढ़ा जाना है और अपीलार्थियों द्वारा इस पर भरोसा किया जाता है:

“4. दिशा-निर्देश

(1) धारा 5 के तहत जारी किया गया कोई भी निर्देश लिखित रूप में होगा।

(2) निर्देश में कार्रवाई की प्रकृति और उस समय को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके भीतर उस व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इसका पालन किया जाएगा जिसे ऐसा निर्देश दिया गया है।

(3) (क) जिस व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को कोई निर्देश जारी करने की मांग की जाती है, उसे प्रस्तावित निर्देश की एक प्रति प्रदान की जाएगी और उसे प्रस्तावित निर्देश जारी करने पर आपत्तियां, यदि कोई हों, इस संबंध में निर्दिष्ट आधिकारिक प्रमाण के साथ नोटिस की सेवा की तारीख से कम से कम पंद्रह दिनों का अवसर दिया जाएगा।

(ख) जहां प्रस्तावित निर्देश किसी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया को चलाने से संबंधित बिजली या पानी या किसी अन्य सेवा को रोकने या विनियमित करने के लिए है और किसी अधिकारी या प्राधिकरण को जारी करने की मांग की जाती है, वहां प्रस्तावित निर्देश की एक प्रति उद्योग, संचालन या प्रक्रिया के अधिभोगियों को भी दी जाएगी, जैसा भी मामला हो और आपत्तियां, यदि कोई हों, तो अधिभोगियों के नेतृत्व में इस संबंध में निर्दिष्ट आधिकारिक प्रमाण के साथ इस नियम के उप-नियम (3 ए) और (4) के तहत प्रक्रियाओं के अनुसार निपटा जाएगा:

बशर्ते कि कब्जाधारी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा यदि उसे पहले ही सुना जा चुका था और ठहराव के लिए उपरोक्त उप-नियम (3 ख) में निर्दिष्ट प्रस्तावित निर्देश या

22 अधिसूचना सं. एस. ओ. 152 (ई) दिनांक 10.02.1988।

बिजली या पानी या किसी अन्य सेवा का विनियमन ऐसी पूर्व सुनवाई के बाद केंद्र सरकार का परिणामी निर्णय था। (4) केंद्र सरकार आपत्तियों की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर, यदि कोई हो या उस तारीख से जब तक व्यक्ति को आपत्तियों को दर्ज करने का अवसर दिया जाता है, जो भी पहले हो, उस व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण से प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद, जिन्हें निर्देशित करने की इच्छा है और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, प्रस्तावित निर्देश को संशोधित करेगी या जारी नहीं करने का निर्णय लेगी।

(5) यदि केंद्र सरकार की राय है कि पर्यावरण को गंभीर नुकसान की संभावना को देखते हुए प्रस्तावित निर्देश के खिलाफ आपत्तियों को दर्ज करने का अवसर प्रदान करना समीचीन नहीं है, तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसा अवसर प्रदान किए बिना निर्देश जारी कर सकती है।

(6) इस नियम के तहत जारी किए जाने वाले प्रत्येक नोटिस या निर्देश को विधिवत रूप से लागू किया गया माना जाएगा।

(क) जहां सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, यदि दस्तावेज कंपनी के नाम से उसके पंजीकृत कार्यालय या उसके प्रमुख कार्यालय या व्यवसाय के स्थान पर संबोधित है और या तो

(i) पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया, या (ii) अपने पंजीकृत कार्यालय या प्रमुख कार्यालय या व्यवसाय के स्थान पर भेजा गया;

(ख) जहां सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक सेवारत सरकारी अधिकारी है, यदि दस्तावेज़ उस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है और उसकी एक प्रति विभाग के इस प्रमुख और सरकार के सचिव को भी दी जाती है, जैसा भी मामला हो, उस विभाग के प्रभारी को भी, जिसमें उस विभाग से संबंधित व्यवसाय का लेन-देन किया जाता है जिसमें अधिकारी कार्यरत है और या तो -

(i) पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, या (ii) उसे दिया जाता है या उसे निविदा दी जाती है;

(ग) किसी अन्य मामले में, यदि दस्तावेज़ उस व्यक्ति को संबोधित है जिसे प्रस्तुत किया जाना है और -

((i) उसे दिया जाता है या उसे निविदा दी जाती है, या 1149

तमिल नाडु और पुडुचेरी पेपर कप मैनुफैक्चर एसोसिएशन बनाम तमिलनाडु राज्य 1150 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

((ii) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जाता है, तो उसके निवास या व्यवसाय के अंतिम ज्ञात स्थान के किसी विशिष्ट भाग पर लगाया जाता है या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दिया जाता है या दिया जाता है या भूमि या भवन के किसी विशिष्ट भाग पर लगाया जाता है, यदि कोई हो, जिससे वह संबंधित है, या (iii) उस व्यक्ति को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है।

स्पष्टीकरण।-इस उप-नियम के उद्देश्य के लिए:-

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें एक निकाय या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है;

(ख) "नौकर" परिवार का सदस्य नहीं है "

(जोर दिया गया)

34. ई. पी. ए. की धारा 5 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह कि राज्य के पास प्रतिबंध लगाने की विधायी क्षमता है-सरकारी आदेश में निहित प्रकार (जिसमें उद्योगों को प्रभावित करने का प्रभाव भी हो सकता है), प्रासंगिक प्रावधानों के अध्ययन से पता चलता है।

35. खेल में अन्य नियम 2016 के नियम हैं जो 'प्लास्टिक' और 'कम्पोस्टेबल प्लास्टिक' की अवहेलना करते हैं:

“प्लास्टिक की सामग्री जिसमें एक आवश्यक घटक के रूप में पॉलीइथिलीन टेरैफ्थैलेट, उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन, विनील, कम घनत्व पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टीरिन रेजिन, बहु-सामग्री जैसे ऐक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, पॉलीफिनाइलिन ऑक्साइड, पॉली

कार्बोनेट, पॉलीब्युटिलीन टेरेफ्थैलेट जैसे उच्च बहुलक होते हैं। 'कम्पोस्टेबल प्लास्टिक' का अर्थ है प्लास्टिक जो कम्पोस्टिंग के दौरान जैविक प्रक्रियाओं द्वारा क्षरण से गुजरता है और पारंपरिक पेट्रो-आधारित प्लास्टिक को छोड़कर अन्य ज्ञात कम्पोस्टेबल सामग्रियों के अनुरूप दर पर CO₂, पानी, अकार्बनिक यौगिकों और बायोमास का उत्पादन करता है, और दृश्यमान, विशिष्ट या विषाक्त अवशेष नहीं छोड़ता है।

36. शुरुआत में, यह इंगित करना भी उचित है कि एनजीटी ने मामले को विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया, इस अदालत को अजीब लगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि ई. पी. ए. की धारा 5 के तहत जारी किए गए आदेश पूरी तरह से एन. जी. टी. के दायरे में आते हैं:

“16. इससे व्यथित कोई भी व्यक्ति,-[.]

“(छ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद जारी किया गया कोई भी निर्देश;

37. उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के प्रश्न पर निर्णय लेते हुए, अधिनियम की धारा 5 के आलोक में, जिसे नियमों के नियम 4 के साथ पढ़ा जाता है, यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि प्रतिबंध केवल 1 (यानी आदेश की तारीख के 6 महीने बाद) को लागू हुआ था, इसलिए याचिकाकर्ता प्रतिबंध के बारे में अच्छी तरह से जानते थे और यहां तक कि ऐसे अभ्यावेदन भी किए थे जिन्हें प्रतिबंध लगाने से पहले सुना और निपटाया गया था। यह देखते हुए कि सभी संबंधितों से व्यक्तिगत नोटिस की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, यह माना गया कि जब इस तरह का नीतिगत निर्णय व्यापक सार्वजनिक हित में लिया जाता है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं होता है।

38. वर्तमान मामले में, उनके प्रतिनिधित्व में भेजे गए पेपर कप संघ को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर मिला और उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया। इसके बाद ही, 08.12.2018 पर, उनके प्रतिनिधित्व को कारणों के साथ निपटाया गया था।

39. नियम 4 का संदर्भ इंगित करता है कि यह अनिवार्य है। इस अदालत ने कई मामलों में निर्णय के बाद की सुनवाई के सवाल पर विचार किया है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए जहां भी कानून उस पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। यह भी एक स्वीकृत सिद्धांत है कि प्राकृतिक न्याय के बारे में किसी कानून या नियम की खामोशी, फिर भी, न्यूनतम सुनवाई की मांग करती है। साथ ही, ऐसे मामले भी हुए हैं, जिनमें अदालत ने निर्णय के बाद सुनवाई की अनुमति दी है: विशेष रूप से लिबर्टी ऑयल मिल्स 23 में। वहाँ अदालत ने माना कि तत्काल या समीचीन कार्रवाई के लिए आपात स्थिति या तत्काल परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जिनमें देरी नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थितियों में, इस अदालत ने निर्णय दिया कि पूर्व सुनवाई के नियम को समाप्त किया जा सकता है। धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड बनाम। सी. सी. ई. 24 ने अभिनिर्धारित

किया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को एक जलडमरूमध्य में नहीं रखा जा सकता है, विशेष रूप से यदि एक निष्पक्ष सुनवाई होगी

23 लिबर्टी ऑयल मिल्स बनाम भारत संघ, (1984) 3 एस. सी. सी. 465

24 (2015) 8 एससीसी 519 1151

तमिल नाडु और पुडुचेरी पेपर कप मैनुफैक्चर एसोसिएशन बनाम तमिल नाडु राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1152

किसी भी घटना में एक ही निर्णय हुआ है।²⁵ 1986 के नियमों के नियम 4 (5) पर करीब से नज़र डालने से पता चलता है कि इसमें समीचीनता के हित में पूर्व सूचना देने के लिए छूट भी शामिल है।

40. वर्तमान मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूर्व-निर्णायक सुनवाई की अनुमति नहीं दी गई थी। फिर भी, अदालत इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकती कि राज्य ने 25.06.2018 पर नियमों को अधिसूचित किया और इसे तुरंत लागू नहीं किया। प्रतिबंध को केवल 01.01.2019 से प्रभावी बनाया गया था। याचिकाकर्ताओं और अन्य पक्षों को प्रतिनिधित्व करने और अपने विचारों को बताने का अवसर दिया गया था, जो उन्होंने किया। निस्संदेह, राज्य ने उन विचारों को स्वीकार नहीं किया। तब सवाल यह है कि क्या इस अदालत को इस बात पर जोर देना चाहिए कि सरकारी आदेश से पहले अवसर देने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रतिबंध ही अमान्य हो जाना चाहिए। यदि कोई इस बात को ध्यान में रखता है कि विवादित सरकारी आदेश द्वारा व्यापक सार्वजनिक हित को कम करने की मांग की गई है, और महत्वपूर्ण रूप से इस परिस्थिति को भी ध्यान में रखता है कि केंद्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.07.2022 के परिणामस्वरूप अन्य उपयोग और प्लास्टिक उत्पादों को फेंकने के बीच एकल उपयोग कप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो सार्वजनिक हित को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

41. इसलिए, इस न्यायालय का मानना है कि हालांकि नियम का अधिदेश पूर्व-निर्णायक सुनवाई का आह्वान करता है, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में, समय के प्रभाव को देखते हुए, अधिसूचना में हस्तक्षेप की स्थिति में जनता को संभावित नुकसान होता है, न्याय के हितों के लिए आवश्यक है कि इस तरह के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अधिसूचना को अमान्य नहीं किया जाना चाहिए।

B. प्रतिबंध पर विचार करते हुए, गुण-दोष के आधार पर

42. अपीलार्थियों की ओर से पेश दोनों वकीलों ने प्रतिबंध के गुण-दोष और क्या राज्य सरकार ने उनके संबंधित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का उचित निर्णय लिया था, इस पर विस्तार से तर्क दिया।

(i) कागज के कप

43. याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि कागज के कप में प्लास्टिक का उपयोग न्यूनतम है (6 प्रतिशत प्लास्टिक और 94 प्रतिशत कागज का अनुपात) और उनके उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध अनुचित, मनमाना और असमान है। विशेषज्ञ निकाय, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के कारण इस मुद्दे की फिर से जांच की गई, अर्थात्

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

याचिकाकर्ताओं के कागज के कप के उपयोग पर प्रतिबंध, प्लास्टिक कोटिंग के साथ प्रबलित, और टी. एन. पी. सी. बी. का बाद का आदेश, दिनांक 8.12.2018, जो विशेष रूप से, निम्नानुसार है:

“प्रतिनिधित्व के आधार पर, संचालन समिति की बैठक के दौरान निर्देशों के अनुसार एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने बताया कि पॉली-कोटेड पेपर कप में 94 प्रतिशत पेपर (सेल्युलोज) और 6 प्रतिशत एल. डी. पी. ई. होता है। इसके अलावा टी. एन. पी. सी. बी. ने सी. आई. पी. ई. टी. में एल. डी. पी. ई. लेपित डिस्पोजेबल पेपर कप नमूनों का परीक्षण किया। सामग्री पहचान केशन परीक्षण विश्लेषण के लिए चेन्नई। सी. आई. पी. ई. टी. के परिणामों के अनुसार, पेपर कप एथिलीन/पॉलीविनाइल/एसीटेट के साथ लेपित पेपर सब्सट्रेट होते हैं जो एक सिंथेटिक पॉलिमर होता है। पॉलीमरिक प्रकृति प्राकृतिक पर्यावरणीय परिस्थितियों में आसानी से अपक्षयी नहीं होती है। तदनुसार, एल. डी. पी. ई. लेपित डिस्पोजेबल पेपर कप प्रतिबंधित हैं और इसलिए प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जा सकता है।

44. आई. आई. टी. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट (जिसके आधार पर पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था) में कहा गया है कि प्रबलित कागज के कपों का सेवन पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा क्योंकि इससे अधिक पेड़ों की कटाई होगी और पुनर्चक्रण से अधिक प्रदूषण होगा। इसने पत्ती उत्पादों, कोरा घास, नारियल से बने उत्पादों, पेंचदार चीड़, मिट्टी के उत्पादों, इस्पात उत्पादों आदि जैसे विकल्पों की भी सिफारिश की। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ने इसी तरह निष्कर्ष निकाला कि सी. आई. पी. ई. टी. परीक्षण पर भरोसा करते हुए एल. डी. पी. ई. कोटिंग के कारण पेपर कप का पुनर्चक्रण लगभग असंभव है।

45. यह कि इन कपों का अंधाधुंध उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है, एक एकल उपयोग उत्पाद के रूप में (अक्सर गर्म पेय पीने के लिए)-किसी आंकड़े की आवश्यकता नहीं है। संरचना के आधार पर, वे गैर-जैव-अपघटनीय हैं, और उनके पुनर्चक्रण में भारी भिन्नता है, क्योंकि इसके लिए कुछ चुनौतियों के नाम देने के लिए उचित संग्रह तंत्र, सख्त पृथक्करण की आवश्यकता होती है। अपीलकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि यह एक प्रभावी सामूहिक तंत्र नहीं होने की स्थिति है, जिसके लिए स्थानीय नगर निगम 2016 के नियमों के अनुसार जिम्मेदार हैं; वे भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। हालाँकि, यह देखते हुए कि प्रतिबंध के लिए वैज्ञानिक आधार है, और सार्वजनिक हित में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों की कई श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने का राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है, इस अदालत के लिए प्रतिबंध के गुण-दोष के आधार पर हस्तक्षेप करने की बहुत कम गुंजाइश या कारण है।

46. इसलिए, यह तर्क कि प्रतिबंध समावेशी और असमान है, इस अदालत की सुविचारित राय में है, प्रबलित पेपर कप के संबंध में नहीं बनाया गया है। अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अपीलार्थी के अधिकार को बिना किसी संदेह के प्रतिबंधित कर दिया गया है; लेकिन आम जनता के व्यापक हित में प्रदूषण मुक्त वातावरण का आनंद लेने के लिए प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के अनुसार उचित था, और इसलिए इसे बरकरार रखा गया है।

((ii) गैर बुने हुए प्लास्टिक के थैले

47. गैर-बुने हुए प्लास्टिक थैलों के प्रतिबंध को एक निर्माता-संघ द्वारा स्पष्टीकरण की मांग के जवाब में दिनांकित 08.12.2018 पत्र में समझाया गया था। पत्र में लिखा था:

“गैर बुने हुए कैरी बैग पॉलीप्रोपाइलीन से बने होते हैं, जो प्राकृतिक वातावरण में आसानी से खराब नहीं होते हैं। इसके अलावा, सामग्री पहचान केशन परीक्षण विश्लेषण के लिए सी. आई. पी. ई. टी., चेन्नई से परीक्षण किए गए गैर-बुने हुए कपड़े कैरी बैग के नमूनों से संकेत मिलता है कि यह एक पॉलीप्रोपाइलीन (सिंथेटिक प्लास्टिक) है। पॉलीमरिक प्रकृति प्राकृतिक पर्यावरणीय परिस्थितियों में आसानी से अपक्षयी नहीं होती है। तदनुसार, गैर बुने हुए पॉलीप्रोपाइलीन कैरी बैग प्रतिबंधित हैं ”

48. इस अदालत की यह सुविचारित राय है कि गैर-बुने हुए थैले के मामले में तर्क थोड़े अलग आधार पर खड़े होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये थैले कुछ हद तक प्रकृति में पुनः प्रयोज्य हैं। इन थैलों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली पॉलीप्रोपीन और फाइलर की उनकी संरचना/अनुपात अनुकूलन योग्य है। इसलिए, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि समग्र प्रतिबंध असमान था। राज्य ने जोर देकर कहा कि कुछ हद तक पुनः प्रयोज्य कहे जाने के बावजूद, उनका अंधाधुंध निपटान किया जाता है और कचरा फैलाता है, जिससे भूजल, मिट्टी की गुणवत्ता आदि को नुकसान होता है, क्योंकि वे ठीक से जैव क्षरण नहीं करते हैं, और इसलिए यह प्रतिबंध को उचित ठहराता है। प्रबलित पेपरकप के विपरीत, ये थैले पुनः प्रयोज्य, पुनर्नवीनीकरण योग्य और कुछ स्तर के जैव क्षरण (संरचना के आधार पर) में सक्षम हैं, लेकिन इसे अधिक बारीकी से देखने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई थी, और वास्तव में इसे स्पष्टीकरण के माध्यम से प्रतिबंध के दायरे में लाया गया था; इस उत्पाद पर प्रतिबंध शायद आगे की जांच के योग्य है।

49. अपीलार्थियों द्वारा दिए गए तर्कों में से एक यह था कि राज्य सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि भारत सरकार ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णयों को देखते हुए 'एकल उपयोग प्लास्टिक' की अवहेलना नहीं की जा सकती है और केंद्र सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ने का संचालन समिति का निर्णय मनमाना और पूर्वाग्रहपूर्ण है। यद्यपि वर्तमान अधिनियम पर लागू नहीं होता है, इसलिए केंद्रीय नियमों में किए गए संशोधनों पर ध्यान देना उचित है। केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति के परिणामस्वरूप एकल उपयोग प्लास्टिक पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दिनांक 19.09.2019 (जिसके कारण 2016 के नियमों में और संशोधन हुए) आई।

50. 2016 के नियमों में 2018, 2021 और 2022 में संशोधन किया गया था। जबकि 2022 के संशोधन 26 ने नियमों में 'बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक' 27 की अवज्ञा को शामिल किया, 2016 के नियमों में 2021 के संशोधन 28 ने 'गैर-बुने हुए थैले' और 'एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तु' के लिए अवज्ञा को शामिल किया जो निम्नानुसार है:

(ना) "गैर-बुने हुए प्लास्टिक बैग" का अर्थ है प्लास्टिक की चादर या उलझे हुए प्लास्टिक फाई बर्स या फाई विलाप के जाल संरचित कपड़े से बना गैर-बुना हुआ प्लास्टिक बैग जो यांत्रिक या थर्मल या रासायनिक साधनों से एक साथ बंधा हुआ है, और "गैर-बुने हुए कपड़े" का अर्थ है एक फल या गुच्छेदार झरझरा चादर जो सीधे प्लास्टिक फाई ब्रेस, पिघले हुए प्लास्टिक या प्लास्टिक फाई ब्रेस से बनाई गई है।

[...]

((क) "एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तु" से ऐसी प्लास्टिक वस्तु अभिप्रेत है जिसका उपयोग निपटान या पुनर्चक्रण से पहले एक ही उद्देश्य के लिए एक बार किया जाना चाहिए;

ये अवज्ञाएं उस समझ के समान हैं जिसे तमिलनाडु राज्य सरकार ने वर्तमान मामले के विषय प्रतिबंध में नियोजित किया था।

26 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) नियम, 2022, जी. एस. आर. 522 (ई) डब्ल्यू. ई. एफ.

27 नियम 3 (एसी)-"बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक" का अर्थ है कम्पोस्टेबल प्लास्टिक के अलावा अन्य प्लास्टिक, जो परिवेशी पर्यावरण (स्थलीय या पानी में) स्थितियों के तहत जैविक प्रक्रियाओं द्वारा क्षरण से गुजरता है, बिना किसी सूक्ष्म प्लास्टिक को छोड़े, या दिखाई देने वाला, या अलग करने योग्य या विषाक्त अवशेष, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित मानकों का पालन करता है।

28 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 जी. एस. आर. 571 (ई), डब्ल्यू. ई. एफ.

1155

तमिल नाडु और पुडुचेरी पेपर कप मैनुफैक्चर एसोसिएशन बनाम तमिल नाडु राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1156

51. 2021 के संशोधन में नियम 4 में एक संशोधन के माध्यम से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं डब्ल्यू. ई. एफ. 01.07.2022 पर इसी तरह का प्रतिबंध भी शामिल किया गया था, जिसमें उपखंड (2), (3) और (4) शामिल किया गया था:

“(1) [...]

(2) 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टीरिन और विस्तारित पॉलीस्टीरिन सहित निम्नलिखित एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।-

(क) प्लास्टिक की छड़ें, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक की छड़ी, कैंडी की छड़ी, आइसक्रीम की छड़ी, सजावट के लिए पॉलीस्टीरिन (थर्मोकोल); (ख) प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, मिठाई के डिब्बों के चारों ओर लपेटना या पैकिंग करना, निमंत्रण पत्र, और सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर।

(3) उप-नियम (2) (बी) के प्रावधान कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

(4) इस अधिसूचना के बाद जारी किए गए पॉलीस्टीरिन और विस्तारित पॉलीस्टीरिन सहित कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी तरह के प्लास्टिक शीट और बहुस्तरीय पैकेजिंग और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के आवरण के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली कोई भी अधिसूचना, इसके प्रकाशन की तारीख से दस साल की समाप्ति के बाद लागू होगी।

52. इसी नियम 4 को उपखंड (1) में भी संशोधित किया गया था, ताकि गैर-बुने हुए प्लास्टिक बैग, डब्ल्यू. ई. एफ. के निर्माण को विनियमित किया जा सके।

“(जे) गैर-बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग 30 सितंबर, 2021 से प्रभावी होने के साथ 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जी. एस. एम.) से कम नहीं होगा।

53. यह देखते हुए कि संशोधित 2016 के नियम अब 60 जी. एस. एम. से ऊपर के गैर-बुने हुए थैलों के निर्माण और उपयोग की अनुमति देते हैं, यानी केंद्र ने इसे प्रतिबंधित करने के बजाय इसे विनियमित करने का एक तरीका खोज लिया है-असंगतता के बारे में अपीलार्थी के तर्क में कुछ योग्यता है। यदि अपीलार्थी के अनुच्छेद 19 (6) के अधिकार पर कम भारी प्रतिबंध संभव है, तो इसका समर्थन किया जाना चाहिए। 2016 के नियमों में संशोधन के संदर्भ में विकास के आलोक में, यह न्यायालय है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

माना जाता है कि गैर-बुने हुए थैलों को एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पादों के प्रतिबंध के भीतर शामिल करने के सवाल को विचार के लिए टी. एन. पी. सी. बी. को वापस भेजना उचित और न्यायसंगत होगा।

54. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, सी. ए. सं. 8536/2022 को एतद्द्वारा निपटाया जाता है, यह देखते हुए कि प्रबलित पेपरकप के प्रतिबंध पर उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। उपरोक्त शर्तों में सी. ए. Nos. 8537-38/2022 की आंशिक रूप से अनुमति है। जिसमें टी. एन. पी. सी. बी. को 2016 के नियमों (संशोधित) के आलोक में गैर-बुने हुए थैलों के मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया गया है। लागत पर कोई आदेश नहीं होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

सी. ए. सं. **8536/2022** निपटाया गया और सी. ए. **Nos. 8537-38/2022**

निधि जैन

आंशिक रूप से अनुमति।